[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

प्रकार की कोई इंडस्ट्री गांव वाले स्थापित कर सकते हैं अथवा वहां पर अपना कोई मकान बना सकते हैं। यह आर्डर उन्होंने कैंसिल कर दिया और जब वहां के एक्जीक्यूटिव कौंसिलर ने इस बात का ध्यान दिलाया तो उन्होंने कहा कि यह बात झूठ है और यह आर्डर कैंसिल नहीं किया गया। इसके बाद एक पत्रकार सम्मेलन में जब एक्जीक्यूटिव कौंसिलर श्री खुराना ने आर्डर पेश कर दिया कि यह आर्डर है जिसमें नीचे लिखा हुआ था कि जितने सर्टीफिकेट दिये गये हैं वे सब रद्द माने जायें तो उन्होंने कहा यह गलत है और मुझे पता लगा है शायद वह आर्डर वापस लिये जा रहे हैं।

जहां कई इंडस्ट्रीज और कई लाख वर्कर्स का सवाल है इसके साथ एक बहुत गहरा सवाल जुड़ा हुआ है जो पालिटिकल है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब से लेफ्टीनेंट गवर्नर नये बने हैं मिस्टर जगमोहन तब से ही उन्होंने तानाशाही शुरू कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि यह तानाशाही जो लाखों लोगों को बेघरबार और बेरोजगार कर रही है क्या यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी अधिकार के अधीन हो रहा है? क्या उनको पता है कि डिप्टी कमिशनर ने जो आर्डर दिया है जिसमें कहा गया है कि गांव का जो डिवलोपमेंट है उसकी जिम्मेदारी डी० डी० ए० को दी जाएगी यह एक म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट के अन्तर्गत करना पड़ता है और यह कानून इस सदन और दूसरे सदन के द्वारा बनाया हुआ है? मुझे सन्देह है कि यह चीज जानबूझ कर की जा रही है। वह यह चाहते हैं कि किसी प्रकार से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कन्फ्रंटेशन कराया जाए। यह कन्फ्रंटेशन यदि हुआ तो यह मानना पड़ेगा कि लेफ्टीनेंट गवर्नर जो आज है वह कांग्रेस पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है सरकारी अफसर के रूप में काम नहीं कर रहा है। मेरी जानकारी यह है कि कल रात्रि को दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल को डिसमिस करने जा रहे थे लेकिन भला हो उन बेचारे अंधों का जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और जिनकी वजह से शायद मेटरोपोलिटन कौंसिल कल रात्रि को बच गई और आज तक जिंदा है।

मैं सदन का ध्यान इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट जानबूझ कर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कन्फ्रंटेशन पैदा कर रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लेफ्टीनेंट गवर्नर जो मेटरोपोलिटन कौंसिल को कन्फ्रंटेशन पैदा करके डिसमिस करना चाहते हैं यह गलत है। अगर आपको डिसमिस करना है तो हिम्मत के साथ कीजिए। इस प्रकार की चीजें करा कर डिसमिस मत करिए। इससे लाखों लोग बेघरबार और बेरोजगार होने जा रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

DR. BHAI MAHAVIR (Madhya Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I have to make a submission. This is a very important question which cannot be disposed by way of a special mention only. I request you that a Calling Attention Motion be admitted. There is a drive towards confrontation between the Delhi Administration and the Central Government, which the Lt. Governor of Delhi seems to be bent on pursuing. Sir, for this you will kindly find some time.

MR. CHAIRMAN: I will consider that.

DR. BHAI MAHAVIR: Yes, please.

REFERENCE TO FAMINE CONDITIONS IN THE CHATTISGARH REGION OF MADHYA PRADESH AND OTHER PARTS OF THE COUNTRY AND ALLEGED BUNGLING BY THE F.C.I. IN DISTRIBUTION OF FOODGRAINS.

श्री लक्ष्मत रत्न कुमारी (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस समय मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ

क्षेत्र छतीसगढ़ अकालग्रस्त है। वहां इस समय इस शताब्दी के सबसे भंयकर अकाल की स्थिति है। यह भी सूचना है कि रायपुर और बिलासपुर डिवीजन के सात जिलों में यह फैला हुआ है। लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं।

फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो खाद्य पदार्थ वहां भेजा है वह इतना खराब और घटिया किस्म का है कि उसे खाकर लोगों के बीमार होने और यहां तक कि मरने के भी समाचार हैं। कहा जाता है कि बहुत से जिलों में लोग घास-फूस और पत्तियां खाकर अपना पेट भर रहे हैं।

एसी स्थिति को देखते हुए कुछ समाज विरोधी तत्वों ने खाद्य पदार्थों को खुले आम काला बाजार में बेचने का धन्धा शुरु कर दिया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन क्षेत्रों में सरकार अपनी देखरेख में बड़े पैमाने पर राहत कार्य उपलब्ध कराये और वहां अविलम्ब पीने के पानी की और खाद्य पदार्थों की व्यवस्था ठीक करे जिससे वहां के लोगों को अपने घर छोड़ कर यहां-वहां भटकने पर मजबूर न होना पड़े।

मैं अभी पिछले दिनों अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने अपने प्रदेश में गई थी। मैंने अकालग्रस्त छोटे किसानों की जो दशा देखी वह बड़ी करुणाजनक है। खाने के लिए रखा हुआ अनाज वे जमीन में बो चुके हैं। अब खाने के अभाव में उनका पूरा कुटुम्ब त्रस्त है। साथ ही लगातार पूरी बरसात में भी पानी न बरसने के कारण पीने के पानी का भी भीषण संकट उपस्थित है। अभी भी जहां तहां अपनी शक्ति भर नालों को बांध कर और कुंओं को साफ कर उन्होंने जो थोड़ा सा पानी प्राप्त किया है उसमें भी कीचड़ आने लगा है। पशु तो वह गन्दा पानी पीते ही हैं, लाचारी में मनुष्य भी वही पीयेंगे। ऐसी दशा में उस गन्दे पानी को पीने के फलस्वरूप महामारी फैलने का डर पैदा हो गया है। बच्चों में मिजिल्स और चिकिन पाक्स फैल गई है। पिछली सरकार ने राहत कार्य खोलने का ढिंढोरा तो खूब पीटा। कहीं-कहीं कुछ कार्य भी खोले, परन्तु वे बीच में ही बन्द कर दिये गये। अब तुरन्त ही पीने के पानी की समस्या को हल करना आवश्यक है। अकालग्रस्त इलाके में युद्ध स्तर पर राहत कार्य करना प्रारंभ होना चाहिए, खासतौर पर जल समस्या का निवारण करना अत्यन्त आवश्यक है। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इस सवाल पर तुरन्त ध्यान दिया जाय क्योंकि यह जन-जीवन से संबंधित समस्या है।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार): श्रीमन् सारे देश में अन्न न होने की वजह से देश के अनेक भागों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है और अन्न न होने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। सब जगह भुखमरी का दृश्य दिखाई दे रहा है। दूसरे शब्दों में जब से यह नई सरकार आई है तब से यह समस्या और भी बढ़ गई है। इसीलिए हम लोग कहा करते थे कि हा-हा कांग्रेस राज, जहां न कपड़ा है न अनाज। यह परिस्थिति पैदा हो गई है। छत्तीसगढ़ के एरियाज में बिहार में, यू० पी० में, मध्य प्रदेश में, हर जगह यह परिस्थिति पैदा हो गई है। इसलिए बुनियादी बात यह है कि देश में जो भी अनाज है, उसका सही रूप से वितरण नहीं होता है। इस सरकार द्वारा बफर-स्टाक का ढोल तो बहुत पीटा जाता है, लेकिन लोगों को अनाज नहीं मिलता है। असलियत यह है कि जिन लोगों को अनाज मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। अफसरों की धांधली की वजह से जिन लोगों के पास अनाज पहुंचाना चाहिए उनके पास नहीं पहुंच पाता है। ये बातें अखबारों में भी आती रहती है हैं। आप धीरज रखिए, मैं उनको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में

[श्री शिव चन्द्र झा]

जो स्थिति है, वही हालत सारे देश की है । राय पुर की यह खबर है—

"More than half its 40 million population is in the grip of the country's worst famine that has hit backward Chhatisgarh in M.P....

An official team visiting Chhatisgarh region found that this was the worst famine of the century, causing misery to 7.7 million people—3.4 million in Raipur Division and 4.3 million in Bilaspur Division."

अब फूड कारपोरेशन में क्या होता है इसको आप जरा सुन लें :

"The foodgrains supplied by the Food Corporation of India are said to be the worst type, let alone being grossly inadequate. In a village near Akaltara in Bilaspur district, a labourer was reported to have died soon after consuming the rice supplied by the FCI, while many others suffered illness.

No rice is being supplied at all to relief centres in Durg district. The same complaint is being voiced from many other relief centres.

People in several distress areas are said to live on grass seeds and "charota bhaji". The consumption of wild roots and fruits in Sarguja district is stated to have resulted in the death of a woman and two children. In the same district, the Sarpanch of a block has alleged 17 starvation deaths and offered to quit office if proved wrong."

सब जगह लोग भुखमरी से मर रहे हैं । यह क्योंकि अखबार में आया है इसलिये पता लगा है परन्तु यह नजरिया सारे देश में मोटे तौर पर है । मेरा सरकार से कहना है कि फूड कारपोरेशन में यह धांधली होती है, राइस की सप्लाई जो जरूरत-मंद लोगों को होनी चाहिए वह नहीं हो रही है । मेरा सरकार से निवेदन है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वह उसे वार-फुटिंग पर करायें और इस बात की जांच करें कि क्या बात है जिससे राइस, चावल जो है वह जरूरत-मंद लोगों को नहीं मिल रहा है और इसके लिये जो आफिसर दोषी हैं उनको तुरन्त सजा दें और डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला फिर से स्ट्रीमलाइन करें, यह मैं सरकार से कहना चाहता हूं ।

STATEMENT BY MINISTER

Reported Burning of Huts of Harijans in Moradabad, Uttar Pradesh

MR. CHAIRMAN: The hon. Home Minister is going to make a statement on the report of burning huts of Harijans in Moradabad, U.P. ...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI LAL K. ADVANI): Before that...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Before I call upon him, I will remind the Members of a rule of procedure of this House, Rule 251.

"A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Chairman but no question shall be asked at the time the statement is made."

But I will allow, in accordance with the practice of this House, clarificatory questions only but no speeches. You can ask for facts and figures and details but please do not make speeches. The hon. Minister.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): I have got a point of order.

(Interruptions)